ont>

Title: Need to protect the interest of farmers in the country- Laid.

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि देश के बड़े उद्योगपतियों को अपने उद्यमों एवं व्यापार के लिए बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं किसानों को 14 प्रतिशत प्रतिर्वा की दर से कर्ज दिया जाता है। हर र्वा बाढ़ और सूखा का सामना कर रहे किसानों की खेती की क्षति होने से उनके लिए समय पर कर्ज की राशि एवं ब्याज का भुगतान करना संभव नहीं हो पाता। उन्हें मूल धन का चक्रवृद्धि ब्याज देना होता है। ऐसे किसानों को सरकार जेल में बंद कर देती है। अपराधियों तक को जेल में सरकारी खर्च पर खाना दिया जाता है लेकिन इन गिरफ्तार किसानों को अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एक कृषि प्रधान देश में, जहां की संसद में साठ प्रतिशत से अधिक किसानों के प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में शीघ्र ही सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।